नमूनार्थ प्रश्नोत्तर पुस्तिका

Sample Question Answer Booklet

Hindi medium

306666

226+10

PAPER CODE GS

PAPER CODE GS

रोल नं. अन्तर्राष्ट्रीय अंकों में

(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 0)

306666

रोल नं शब्दों में लिखे Suraj Alhapuriya

अभ्यर्थी द्वारा सावधानी पूर्वक भरा जावें

V. good

अभ्यर्थी के अनुक्रमांक एवं पहचान पत्र को प्रवेशपत्र से मिलान पश्चात् ही वीक्षक बॉक्स में हस्ताक्षर करें

वीक्षक द्वारा भरा जावें

नमूनार्थ प्रश्नोत्तर पुस्तिका
Sample Question
Answer Booklet

प्रश्नोत्तर पुस्तिका बारकोड /QR CODE/ Page No. 1

IMPORTANT NOTES
महत्वपूर्ण निर्देश

(A) प्रश्नोंत्तर पुस्तिका में प्रश्न हल करने से पूर्व उसके संलग्न ओ.एम.आर. पत्रक को भली प्रकार से भर लें।
Please fill up the OMR Sheet of this Question- Answer Booklet properly before answering.

(B) हिन्दी व्याकरण/हिन्द निबंध के प्रश्नपत्र को छोड़कर अन्य सभी प्रश्नों का हिन्दी अथवा अंग्रेजी में उत्तर लिखा जा सकता है। Except Hindi Grammar/Hindi Essay question paper, all other question papers can be written either in Hindi or English language.

(C) अभ्यर्थियों को अपने उत्तर निर्धारित शब्दों की सीमा से अधिक नहीं लिखना चाहिए। इसका उल्लंघन करने पर अंक काटे जाएँगे। The candidates should not write then answer beyond the prescribed limit of word; failing which marks will be deducted.

(D) प्रत्येक प्रश्न का उत्तर प्रश्नोत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान पर ही लिखें। प्रश्नोत्तर पुस्तिका (रफ कार्य के पृष्ठ सहित) के अंदर किसी भाग पर अनुक्रमांक अपना नाम नाम अन्य कोई नाम, पता या अन्य कोई पहचान चिह्न अंकित न करें। उत्तर पुस्तिका के साथ अन्य कोई सामग्री संलग्न करना भी वर्जितहै। इन निर्देशों का उल्लघंन करने पर आवेदक को कोई नोटिस दिये बिना उसकी उम्मीदवारी निरस्त की जा सकेगी।
Please write answer only in the prescribed space of booklet. Do not make any mark of identity inside the booklet (including rough paper page) like roll number, name, any other name, address or such other mark. Do not enclose anything with the answer booklet. The candidature of candidates violating these instructions would be cancelled without even giving them any other notices.

(E) अभ्यर्थियों को निर्देशित किया जाता है कि प्रश्नोत्तर पुस्तिका में प्रत्येक पृष्ठ में बनाई गई बार्डर लाईन से बाहर प्रत्युत्तर नहीं लिखे। बार्डर लाइन के बाहर लिखे गये उत्तर को परीक्षक द्वारा जाँचा नहीं जाएगा।
Candidates are directed that they should not write (answer) outside the border line in every page. Answer written outside the border line will not be checked by the Examiner.

(F) यदि किसी प्रश्न में किसी प्रकार की कोई मुद्रण या तथ्यात्मक प्रकार की त्रुटि हो प्रश्न के हिन्दी तथा अंग्रेजी रुपान्तरों में से हिन्दी रुपान्तरों में से हिन्दी रुपान्तर मान्य होगा। If there is any sort of ambiguity/mistake either of printing or of factual nature then out of Hindi and English version of the question, the Hindi version will be treated as standard.

(G) अभ्यर्थी को प्रश्नोत्तर पुस्तिका सीलबंद लिफाफे में प्रदान की गई है। अभ्यर्थी लिफाफे पर अंकित निर्देशों को पढ़कर घोषणा पर हस्ताक्षर कर लें ओर उसे वीक्षक को वापस कर दें।
The Question-Answer Booklet is provided in a sealed envelope to the candidate. Candidate must sign the declaration as per direction printed on the envelope and return it to the invigilator.

(H) अभ्यर्थी प्रश्नोत्तर पुस्तिका के ऊपर संलग्न इस ओ.एम.आर पत्रक पर सभी वांछित विवरण नीले/कालेबाल पेन से सावधानी पूर्वक भरें। ध्यान रखे कि यह ओ.एम.आर.पत्रक कहीं से कटे–फटे नहीं अथवा किसी भी प्रकार से क्षतिग्रस्त नही हों।
Candidate should fill up all desired details on this attached OMR sheet of Question-Answer Booklet with blue/black ball point pen. Please ensure that this OMR Sheet is not turn or Damaged.

(I) यह ओ.एम.आर पत्रक दो भागों में बंटा है, जिसमें कतिपय सूचनाएँ पूर्व मुद्रित है। शेष की पूर्ति अभ्यर्थी को करनी है। This OMR Sheet consists of two parts in which some information is pre-printed: remaining details have to be filled by the candidates.

(J) यदि प्रश्नोत्तर पुस्तिका कहीं से कटी फटी या अमुद्रित है तो तत्काल वीक्षक के ध्यान में ला दें। उसे बदलवा दें, अन्यथा उसका दायित्व अभ्यर्थी का होगा। If the Question-Answer Booklet is turn or not printed properly, immediately bring it to notice of invigilator and get changed the Question-Answer Booklet otherwise the candidate will be liable for that.

विशेष नोट: अभ्यर्थी द्वारा यदि ओ.एम.आर पत्रक पर गलत सूचना भरी जाती है या उसे किसी प्रकार की क्षति पहुँचाई जाती है तो आयोग द्वारा संपूर्ण परीक्षा हेतु अभ्यर्थिता निरस्त की जा सकेगी और उसके लिए अभ्यर्थी स्वंय उत्तरदायी होगा।

Special Note: If there is any wrong information filled by the candidate then his candidature of the entire examination shall be rejected by the commission for which he himself will be liable.

खण्ड – अ

प्रश्न.1 इस प्रश्न में 15 अति लघु उत्तरीय उप प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर अधिकतम 10 शब्दों में देना है। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न 03 (तीन) अंक का है।

Que.1 This question contains 15 very short answer type sub questions. Answer each question in maximum 10 words. All questions are compulsory. Each question carries 03 (Three) Marks.

प्रश्न. 1.1 संवैधानिक सरकार

उत्तर – संविधान के उपबंधों के तहत गठित, नियमित व नियंत्रित एवं विधि द्वारा संचालित सरकार।
– इसे सीमित या उत्तरदायी सरकार भी कहते हैं। (3)

प्रश्न. 1.2

उत्तर – संवैधानिक मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता संवैधानिक नैतिकता है।
– मूल्यों जैसे – बंधुत्व, समानता, न्याय का प्रभावी अनुपालन, (2½)
डॉ अम्बेडकर – नागरिक वर्गों व प्रशासनिक समूहों के परस्पर विरोधी हितों के मध्य शब्द सीमा का ध्यान रखें। समन्वय।

प्रश्न. 1.3 संघवाद

उत्तर – किसी देश की अवयव इकाईयों व केन्द्रीय शक्ति के बीच सत्ता का समविभाजन। – भारतीय संघवाद कनाडा से लिया गया, (3)
– इस आर बोम्मई वाद 1994 – भारतीय संविधान संघीय संविधान है।

प्रश्न.1 इस प्रश्न में 15 अति लघु उत्तरीय उप प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर अधिकतम 10 शब्दों में देना है। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न 03 (तीन) अंक का है।

Que.1 This question contains 15 very short answer type sub questions. Answer each question in maximum 10 words. All questions are compulsory. Each question carries 03 (Three) Marks.

प्रश्न. 1.4

उत्तर समाजवादी भावनाओं वाले - बहुमत का शासन, नियतकालीन चुनाव व नागरिक संप्रभुता जैसे तत्वों को वरीयता देने वाला संविधान समाजवादी संविधान है।

(3)

प्रश्न. 1.5

उत्तर भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार, भारत के संविधान के शक्ति के स्रोत 'भारत के लोग' है, संविधान देश के नागरिकों से शक्ति अधिग्रहित करता है।

(3)

प्रश्न. ~~1.6~~ 1.7

उत्तर - भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 व 36 में परिभाषित,
- 'राज्य' - संप्रभुता का द्योतक है, देश के लोग, क्षेत्रफल, प्रशासन व्यवस्था राज्य का निर्माण करते है।

(3)

प्रश्न.1 इस प्रश्न में 15 अति लघु उत्तरीय उप प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर अधिकतम 10 शब्दों में देना है। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न 03 (तीन) अंक का है।

Que.1 This question contains 15 very short answer type sub questions. Answer each question in maximum 10 words. All questions are compulsory. Each question carries 03 (Three) Marks.

प्रश्न. ~~1.7~~ 1.6

उत्तर ~~एक ऐसी राजनीतिक विचारधारा जो राजनीतिक लोकतंत्र के साथ उत्पादन व वितरण के साधनों पर सामाजिक स्वामित्व की वकालत करती है, आर्थिक प्रणाली पर लोकतांत्रिक नियंत्रण।~~ (3)

प्रश्न. 1.8

उत्तर ~~संविधान निर्माण 29 समितियों में से एक, मसौदा समिति की अध्यक्षता डा अम्बेडकर द्वारा की गई, कुल सदस्य - 7, गठन - 29 अगस्त 1947, मसौदा तैयार - 4 नवंबर 1947~~ (3)

प्रश्न. 1.9

उत्तर ~~(1) राज्य का प्रमुख प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित,~~
~~(2) वास्तविक प्रमुख व नाममात्र प्रमुख अलग - अलग,~~
~~(3) विशेषाधिकार वर्ग की समाप्ति व पद वंशानुगत नहीं,~~ (3)

प्रश्न.1 इस प्रश्न में 15 अति लघु उत्तरीय उप प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर अधिकतम 10 शब्दों में देना है। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न 03 (तीन) अंक का है।

Que.1 This question contains 15 very short answer type sub questions. Answer each question in maximum 10 words. All questions are compulsory. Each question carries 03 (Three) Marks.

प्रश्न.1. 10 शक्ति का विभाजन

उत्तर
- ~~भारतीय संविधान के मूल ढाँचे का महत्वपूर्ण तत्व,~~
- ~~केन्द्र व राज्य के मध्य अनुच्छेद -246 व सातवीं अनुसूची के माध्यम से विधायी शक्तियों का बँटवारा, अलग व संतुलन किया,~~

प्रश्न.1.11

उत्तर
- ~~साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद ही राष्ट्रीय आय है,~~
- ~~$NNP_{fc} = NNP_{MP} - IDT + सब्सिडी$~~
- ~~राष्ट्रीय गणना के तीन विधियाँ है - (1) आय विधि (2) व्यय विधि (3) उत्पाद विधि~~

तीनों विधियाँ नहीं लिखी है

प्रश्न.1.12

उत्तर
- ~~किसी देश के अर्थव्यवस्था में उत्पादन प्रक्रिया में प्रयुक्त सेवाओं द्वारा उत्पन्न आय कारक आय कहलाती है,~~
- ~~भूमि, श्रम, पूँजी, उद्यम → किराया, वेतन, ब्याज, लाभ~~

उत्पादन सेवाएँ — कारक आय

शब्द सीमा

नमूनार्थ प्रश्नोत्तर पुस्तिका
Sample Question
Answer Booklet

प्रश्नोत्तर पुस्तिका बारकोड / QR CODE/ Page No. 7

प्रश्न.1 इस प्रश्न में 15 अति लघु उत्तरीय उप प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर अधिकतम 10 शब्दों में देना है। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न 03 (तीन) अंक का है।

Que.1 This question contains 15 very short answer type sub questions. Answer each question in maximum 10 words. All questions are compulsory. Each question carries 03 (Three) Marks.

प्रश्न.1.13

उत्तर किसी देश की घरेलू सीमा के भीतर एक वित्तीय वर्ष में अंतिम रूप से उत्पादित वस्तु एवं सेवाओं के कुल मौद्रिक मूल्य को उस देश की सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं, (3)

प्रश्न.1.14

उत्तर GNP – Gross national product
पूरा नाम - सकल राष्ट्रीय आय - किसी देश के सामान्य निवासी द्वारा किसी देश की घरेलू सीमा के भीतर व बाहर अंतिम एक वित्तीय वर्ष के दौरान अंतिम रूप से उत्पादित वस्तु एवं सेवाओं के कुल मौद्रिक मूल्य से है, $GNP = GDP + (X - M)$ (1 1/2)

प्रश्न.1.15

उत्तर कारक लागत पर जीएनपी से तात्पर्य - बाजार लागत पर जीएनपी में अप्रत्यक्ष कर घटाकर व सब्सिडी जोड़कर प्राप्त मूल्य से है, $GNP_{FC} = GNP_{MP} - IDT + \text{सब्सिडी}$ (3)

प्रश्न.2 इस प्रश्न में 10 लघुउत्तरीय उपप्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर अधिकतम 50 शब्दों में देना है। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न 05 (पाँच) अंक का है।

Que.2 This question contains 10 short answer type sub questions. Answer the question in maximum 50 words. All questions are compulsory. Each question carries 05 (Five) Marks.

प्रश्न. 2.1

उत्तर भारत में अदालतों की प्राधिकारिता से आशय विधि के निर्वचन, व्याख्या व विवादों के निपटान संबंधी अधिकार व शक्ति से है। भारत में एकीकृत न्यायालिका है, किन्तु फिर भी न्यायालयों के पृथक परिभाषित प्राधिकारिता है,

सर्वोच्च न्यायालय	उच्च न्यायालय	अधीनस्थ न्यायालय
अनु-131 - प्रारंभिक क्षेत्राधिकार	अनु-226 - प्रादेशिक व रिट प्राधिकारिता	- दीवानी मामलों व फौजदारी मामलों में 7 वर्ष तक के कारावास की सजा देने की शक्ति।
अनु- 132, 133, 134, 136 अपीलीय क्षेत्राधिकार।	अनु-227 - अधीक्षण न्यायालय,	
अनु- 137 पुनर्विलोकनकारी,		
अनु 143 - परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार।	अधीक्षण, प्रशासनिक क्षेत्राधिकार	

5 V. good.

प्रश्न.2 इस प्रश्न में 10 लघुउत्तरीय उपप्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर अधिकतम 50 शब्दों में देना है। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न 05 (पाँच) अंक का है।

Que.2 This question contains 5 short answer type sub questions. Answer the question in maximum 50 words. All questions are compulsory. Each question carries 05 (Five) Marks.

प्रश्न.2.2

उत्तर भारतीय संविधान भाग-3 के अंतर्गत नागरिकों को वैधानिक स्वतंत्रता के रूप में मौलिक अधिकार देता है, किन्तु इनकी उपबंधों के अंतर्गत कुछ पर प्रतिबंध लगाया है,

(1) अनुच्छेद -15 - धर्म, लिंग, जाति, मूलवंश व जन्मस्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध, किन्तु 15(3) महिलाओं व बच्चों के संबंध में विशेष उपबंध करता है।

(2) अनुच्छेद -16 - लोक नियोजन में अवसर की समानता किन्तु अनुच्छेद -16(4) - वंचित वर्गों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करता है,

(3) अनुच्छेद -19(1) के तहत छः तरह की स्वतंत्रताएँ दी गई किन्तु अनु 19(3) के तहत राज्य कितना अभंसा के आधार पर 19(3) आनुपातिक निर्बंधन की पहचान करता है।

नमूनार्थ प्रश्नोत्तर पुस्तिका
Sample Question
Answer Booklet

प्रश्न. 2 इस प्रश्न में 10 लघुउत्तरीय उपप्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर अधिकतम 50 शब्दों में देना है। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न 05 (पाँच) अंक का है।

Que.2 This question contains 10 short answer type sub questions. Answer the question in maximum 50 words. All questions are compulsory. Each question carries 05 (Five) Marks.

प्रश्न. 2.3

उत्तर समाजवाद 20वीं शताब्दी में उत्पन्न विचारधारा है, भारतीय परिप्रेक्ष्य में समाजवाद गाँधीवाद व मार्क्सवाद का मिला जुला रूप है जो गाँधीवाद की तरफ अधिक झुकाव रखता है,
- भारतीय समाजवाद मूलतः 'लोकतांत्रिक समाजवाद' है,
- सर्वोच्च न्यायालय के शब्दों में "भारतीय समाजवाद गरीबी, आर्थिक असमानता का समाप्त करने की परिकल्पना करता है," - वर्ष 1991 के बाद 'उदारवादी समाजवाद'
- निजी संपत्ति का न्यूनतम व उत्पादन व वितरण के साधनों पर सार्वजनिक नियंत्रण इसका मूल रूप है।

5

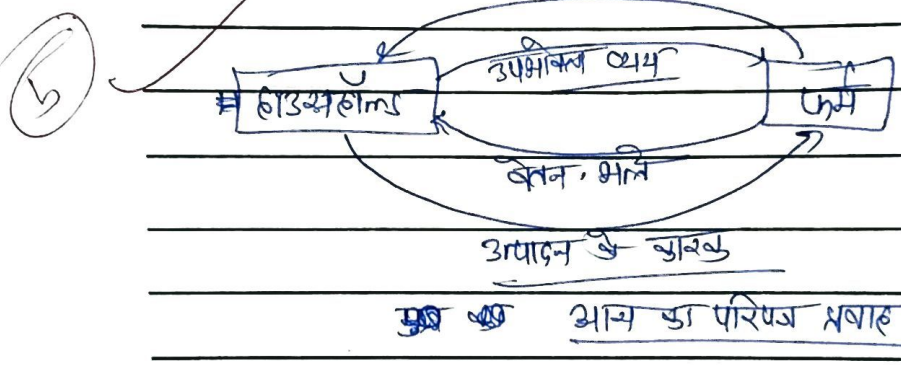
प्रश्न.2 इस प्रश्न में 10 लघुउत्तरीय उपप्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर अधिकतम 50 शब्दों में देना है। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न 05 (पाँच) अंक का है.

Que.2 This question contains 10 short answer type sub questions. Answer the question in maximum 50 words. All questions are compulsory. Each question carries 05 (Five) Marks.

प्रश्न.2.4

उत्तर

अर्थव्यवस्था का वह मॉडल जिसमें आर्थिक अभिकर्ताओं के मध्य मुद्रा का प्रवाह व वस्तु एवं सेवाओं का विनिमय एक बंद परिपथ में संपन्न होता है



प्रश्न.2 इस प्रश्न में 10 लघुउत्तरीय उपप्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर अधिकतम 50 शब्दों में देना है। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न 10 (पाँच) अंक का है।

Que.2 This question contains 5 short answer type sub questions. Answer the question in maximum 50 words. All questions are compulsory. Each question carries 05 (Five) Marks.

प्रश्न. 2.5

उत्तर

बारह आय – आर्थिक प्रणाली में उत्पादन के साधनों भूमि, श्रम, पूँजी, व उद्यम द्वारा उत्पन्न आय बारह आय कहलाती है,

बारह सेवाएं – बारह आय

भूमि – किराया
श्रम – वेतन
पूँजी – ब्याज
उद्यम – लाभ

बारह आय इसे ही राष्ट्रीय आय गणना की आय विधि कहते है,

प्रश्न.2 इस प्रश्न में 10 लघुउत्तरीय उपप्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर अधिकतम 50 शब्दों में देना है। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न 05 (पाँच) अंक का है।

Que.2 This question contains 10 short answer type sub questions. Answer the question in maximum 50 words. All questions are compulsory. Each question carries 05 (Five) Marks.

प्रश्न. 2.6

उत्तर 52 वें संविधान संशोधन को दल बदल विरोधी कानून के रूप में संसद द्वारा वर्ष 1985 में संविधानसंशोधन प्रावधान ① राजनीतिक दल का सदस्य स्वेच्छा अपने दल से स्वैच्छिक त्यागपत्र दे तो वह सदस्यता से अयोग्य घोषित, ② निर्दलीय उम्मीदवार, चुनाव जीत पश्चात किसी दल की सदस्यता ग्रहण ले तो अयोग्य घोषित, ③ नामांकित सदस्य - अपने मनोनयन के 6 माह पश्चात सदस्यता ले, 91 वें संविधान संशोधन प्रावधान ① मंत्रिपरिषद के सदस्यों की संख्या लोकसभा सदस्यों की संख्या के 15% से अधिक नहीं, ② दल बदल के मामले में दूर का प्रावधान समाप्त हटाने अनुमति,

(12) (6)

2002

प्रश्न. 2 इस प्रश्न में 10 लघुउत्तरीय उपप्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर अधिकतम 50 शब्दों में देना है। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न 05 (पाँच) अंक का है।

Que.2 This question contains 10 short answer type sub questions. Answer the question in maximum 50 words. All questions are compulsory. Each question carries 05 (Five) Marks.

प्रश्न. 2.7

उत्तर

42वें संविधान संशोधन की प्रमुख विशेषताएँ निम्न हैं;

(1) प्रस्तावना में तीन शब्द - समाजवाद, पंथनिरपेक्षता व अखंडता जोड़े गए।

(2) सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर - मूल कर्तव्यों को नए भाग IV (A) में जोड़ा गया

(3) राज्य के नीति निदेशक तत्वों में तीन नए प्रावधान - 39(A), 43(A) व 48(A) जोड़ा गया।

(4) राष्ट्रपति को केबिनेट की सलाह मानने के लिए बाध्य किया गया।

(5) संविधान संशोधन को न्यायिक समीक्षा से बाहर किया गया।

प्रश्न.2 इस प्रश्न में 10 लघुउत्तरीय उपप्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर अधिकतम 50 शब्दों में देना है। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न 05 (पाँच) अंक का है।

Que.2 This question contains 10 short answer type sub questions. Answer the question in maximum 50 words. All questions are compulsory. Each question carries 05 (Five) Marks.

प्रश्न. 2.8

उत्तर भारतीय संविधान के भाग-3 में वर्णित मौलिक अधिकार संविधान निम्न है, जिनकी संख्या 6 है,

(1) समता का अधिकार (अनु- 14-18)
(2) स्वतंत्रता का अधिकार (अनु- 19-22)
(3) शोषण के विरुद्ध अधिकार (अनु- 23, 24)
(4) धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार (अनु- 25-28)
(5) संस्कृति व शिक्षा का अधिकार (अनु- 29-30)
(6) संवैधानिक उपचारों का अधिकार (अनु- 32)

4½

प्रश्न.2 इस प्रश्न में 10 लघुउत्तरीय उपप्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर अधिकतम 50 शब्दों में देना है। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न 05 (पाँच) अंक का है।

Que.2 This question contains 10 short answer type sub questions. Answer the question in maximum 50 words. All questions are compulsory. Each question carries 05 (Five) Marks.

प्रश्न. 2.9

उत्तर

मौलिक अधिकार	नीति निदेशक तत्व
(1) न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय है।	(1) न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है।
(2) व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास को सुनिश्चित करते हैं	(2) सामुदायिक विकास को सुनिश्चित करते हैं
(3) लागू करने की विधि ~~आवश्यकता~~ नहीं स्वतः लागू	(3) लागू कराने विधि की आवश्यकता होती है
(4) देश में ~~गणतांत्रिक~~ लोकतंत्र सुनिश्चित करते हैं	(4) देश में सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र सुनिश्चित करते हैं
(5) ~~प्रवर्तन~~ न्यायोचित	(5) गैर न्यायोचित

प्रश्न.2 इस प्रश्न में 10 लघूत्तरीय उपप्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर अधिकतम 50 शब्दों में देना है। सभी प्रश्न अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न 05 (पाँच) अंक का है।

Que.2 This question contains 10 short answer type sub questions. Answer the question in maximum 50 words. All questions are compulsory. Each question carries 05 (Five) Marks.

प्रश्न. 2.10

उत्तर भारतीय संविधान के भाग-3 में अनुच्छेद-14 के तहत वर्णित प्रावधान, संकल्पना प्रिंटेड में दी गई है।

विधि के समक्ष समता - अर्थात

(1) विशेषाधिकारों की समाप्ति,

(2) विधि सर्वोपरि है,

इस अवधारणा के अंतर्गत देश के प्रावधान प्रत्येक वर्ग के लिए समान होंगे यह वर्गों के लिए पृथक् विधान की बात नहीं करता, विधि के द्वारा प्रत्येक नागरिक के केवल धर्म, जाति, लिंग कुलवंश व जन्मस्थान के आधार पर भेद नहीं किया जाएगा।

प्रश्न.3 इस प्रश्न में 5 दीर्घउत्तरीय या निबंधात्मक उपप्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर अधिकतम 200 शब्दों में देना है। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न 11 (ग्यारह) अंक का है।

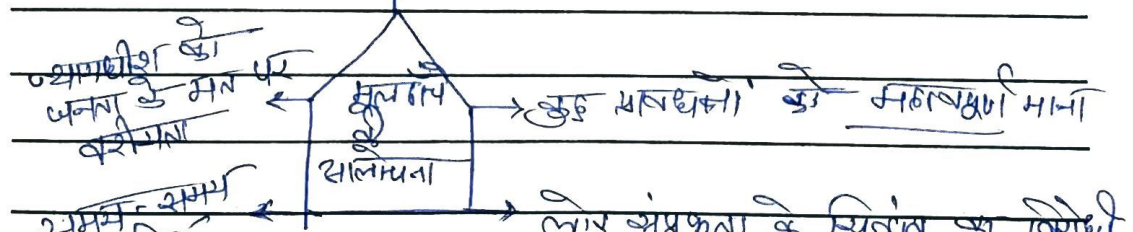
Que. 3 This question contains 5 long answer or essay type sub questions. Answer each question in maximum 200 words. All questions are compulsory. Each question carries 11 (Eleven) Marks.

प्रश्न. 3.1

उत्तर

भारतीय संविधान के प्रावधानों की प्रगतिशील व्याख्या व उनके दीर्घकालिक महत्व को ध्यान में रखते हुए न्यायपालिका द्वारा कार्यपालिका की निरंकुशता से बचने के लिए मूल ढाँचे की संकल्पना का प्रतिपादन, केशवानंद भारती मामले में वर्ष 1973 में किया।

मूल ढाँचे का संविधान में उल्लेख नहीं।



- मूल ढाँचे के सिद्धांत का उल्लेख संविधान में नहीं किया गया है, अपितु न ही अनुच्छेद 368 संसद की संशोधनकारी शक्ति को सीमित करता है।

- मूल ढाँचे का प्रावधान संविधान के कुछ प्रावधानों को तो पर्याप्तता पूर्ण बनाता है किन्तु कुछ प्रावधानों को सीमित नहीं देता है।

- न्यायाधीशों द्वारा मूल ढाँचे की व्याख्या लोगों के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों पर प्रभुत्व को इंगित करता है।

(5) - मूल ढाँचे का सिद्धांत चिरस्थायी नहीं है, न्यायपालिका समय-समय पर इसके अंतर्गत नए प्रावधानों को जोड़कर मूल ढाँचे का नया रूप प्रस्तुत करती है।

- मूल ढाँचे का सिद्धांत लोकतंत्रता का विरोधी है,

अतः न्यायपालिका कार्यपालिका को निरंकुश होने से बचाने के लिए मूल ढाँचे के सिद्धांत जैसी संकल्पना को जन्म दिया साथ ही साथ संविधान के दीर्घकालिक महत्व के प्रावधानों को भी संरक्षण प्रदान किया।

प्रश्न.3 इस प्रश्न में 5 दीर्घउत्तरीय या निबंधात्मक उपप्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर अधिकतम 200 शब्दों में देना है। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न 11 (ग्यारह) अंक का है।

Que. 3 This question contains 5 long answer or essay type sub questions. Answer each question in maximum 200 words. All questions are compulsory. Each question carries 11 (Eleven) Marks.

प्रश्न. 3.2

उत्तर

भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निहित लक्ष्य भारतीय संविधान सभा की उद्देशिका, दूरदर्शिता व बुद्धिमत्ता को इंगित करते हैं, इन ध्येयों की स्पष्ट प्राप्ति की स्पष्ट मंशा संविधान की उद्देशिका में वर्णित तत्वों से दृष्टिगोचर होती है, भारतीय संविधान के निम्न उद्देश्य हैं,

(10)

न्याय → सामाजिक → सामाजिक दर्जा कुछ भी हो
→ आर्थिक → आर्थिक असमानता समाप्त करना
→ राजनैतिक → वोट देने का अधिकार,

समता → प्रतिष्ठा व अवसर की समानता → अनुच्छेद - 14, 15, 16, 17 व 18 स्पष्ट रूप से समानता को स्थापित करने की पहल करते हैं,

स्वतंत्रता → विचार
→ अभिव्यक्ति
→ विश्वास
→ धर्म
→ उपासना

भारतीय संविधान अपने नागरिकों को बेरोकटोक अपनी गतिविधियाँ, विधि के दायरे में रहते हुए संचालित करने का अधिकार देता है।

बंधुता → व्यक्ति की गरिमा व राष्ट्र की एकता व अखंडता को सुनिश्चित करने वाली भावना को बंधुत्व के रूप में सम्मिलित किया गया।

अतः भारतीय संविधान देश के नागरिकों के ~~मध्य~~ मध्य सामाजिक, आर्थिक व राजनैतिक लोकतंत्र को स्थापित करने का प्रयास करता है एवं संघीय व्यक्ति भारत के लोगों को प्रतिनिधित्व करता है।

good

प्रश्न.3 इस प्रश्न में 5 दीर्घउत्तरीय या निबंधात्मक उपप्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर अधिकतम 200 शब्दों में देना है। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न 11 (ग्यारह) अंक का है।

Que. 3 This question contains 5 long answer or essay type sub questions. Answer each question in maximum 200 words. All questions are compulsory. Each question carries 11 (Eleven) Marks.

प्रश्न. 3.3

उत्तर

भारतीय संविधान के भाग-3 में वर्णित मौलिक अधिकार राज्य की लोकतंत्र स्थापित करने की पहल करते हैं, जबकि भारतीय संविधान के भाग-4 में अनु- 36-51 के मध्य प्रावधानित राज्य के नीति निदेशक तत्व देश में सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र सुनिश्चित करते हैं।

मूल अधिकारों व नीति निदेशक तत्वों के मध्य संबंध -

असमानता - मूल अधिकार अपनी प्रकृति में न्यायालय द्वारा न्यायोचित व प्रवर्तनीय है, जबकि नीति निदेशक तत्वों के लिए न्यायालय के समक्ष चुनौती नहीं दी जा सकती अतः यह अपनी प्रकृति में गैर न्यायोचित है।

मूल अधिकार व नीति निदेशक तत्वों के मध्य संबंध की सही व्याख्या निम्न बिंदुओं के माध्यम से समझी जा सकती है,

(1) 1951 ई. में चम्पकम दोराईराजन एवं केरल राज्य मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने मूल अधिकारों को नीति निदेशक तत्वों पर वरीयता दी,

(2) 1967 ई. गोलक नाथ राज्य सिंहावाद में सर्वोच्च न्यायालय ने 'हारमोनियस कंस्ट्रक्शन' का सिद्धांत प्रतिपादित किया व दोनों के मध्य समानांतर संबंध बताया।

(3) दो कानूनों प्रीवी पर्स इन्सूलन व बैंक राष्ट्रीयकरण अध्यादेशम लाया जाने पर अनु 19 व 31 के बीच हो रहा था, जिन्हें सर्वोच्च न्यायालय ने इन्हें असंवैधानिक बताया,

(4) 25वां संविधान संशोधन - अनु 31(C) जोड़ा,

(5) केशवानंद भारती वाद - ✓

(6) मिनर्वा मिल्स वाद - मूल अधिकार व नीति निदेशक तत्वों के मध्य संतुलन', वर्तमान में 31(B) व 31(C) छोड़कर अन्य मूल अधिकार DPSP के पर वरीयता प्राप्त है।

प्रश्न.3 इस प्रश्न में 5 दीर्घउत्तरीय या निबंधात्मक उपप्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर अधिकतम 200 शब्दों में देना है। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न 11 (ग्यारह) अंक का है।

Que. 3 This question contains 5 long answer or essay type sub questions. Answer each question in maximum 200 words. All questions are compulsory. Each question carries 11 (Eleven) Marks.

प्रश्न. 3.4

उत्तर

मूल अधिकारों को 'भारत का मैग्नाकार्टा' कहा जाता है जिन्हे संविधान के अनुच्छेद 12-35 के मध्य व्यक्तित्व के विकास को बढ़ावा देने वाले सिद्धांतों के रूप में परिभाषित किया गया, किन्तु ये पर निर्भर कुछ विशेष परिस्थितियों में आरोपित किया जा सकता है।

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 358, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 19 के तहत दी गई इन स्वतंत्रताओं के स्वत: निलंबन की बात करता है; अत: यदि ये अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल देश या देश के किसी भाग में प्रवर्तनीय है तो अनुच्छेद 19(1) के तहत दी गई इन स्वतंत्रताएँ स्वत: निलंबित हो जाएँगी।

अनुच्छेद - 359 के तहत, यदि अनुच्छेद 352 प्रवर्तनीय हो तब अनुच्छेद 20, 21 के अतिरिक्त अन्य मौलिक अधिकार संसद राष्ट्रपति के आदेश द्वारा निलंबित किए जा सकते हैं, जिसमें वह मूल अधिकार का उल्लेख व उस तिथी का भी उल्लेख करेगा जिस तिथि तक मूल अधिकार निलंबित रहेगा।

(8)

मार्शल लॉ के तहत अनुच्छेद 34 यदि प्रवर्तनीय हो तब नागरिकों को दिए गए इन अधिकार निलंबित किए जा सकते है।

अतः कुछ विशेष परिस्थितियों में मूल अधिकारों के निलंबन के प्रावधान संविधान के द्वारा तहत किए है।

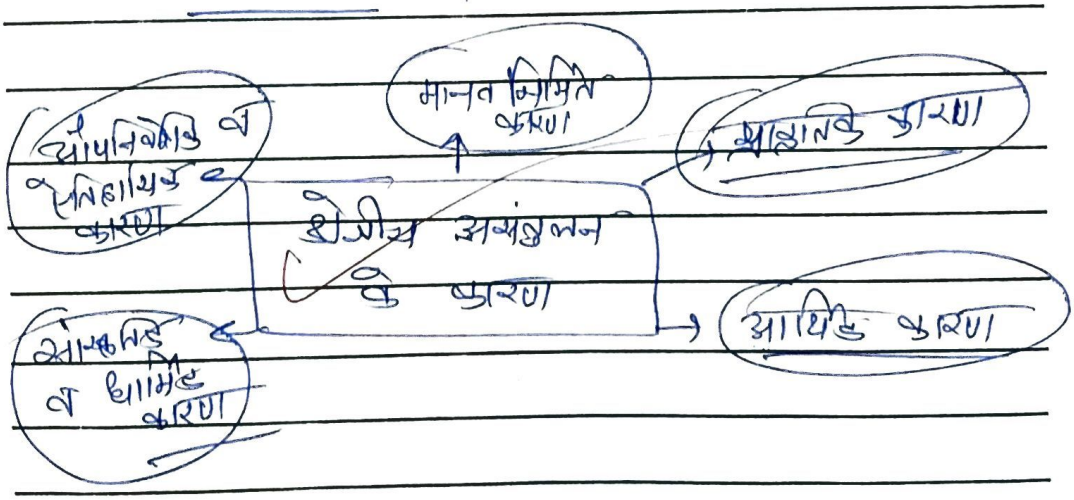
प्रश्न.3 इस प्रश्न में 5 दीर्घउत्तरीय या निबंधात्मक उपप्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर अधिकतम 200 शब्दों में देना है। सभी प्रश्न अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न 11 (ग्यारह) अंक का है।

Que. 3 This question contains 5 long answer or essay type sub questions. Answer each question in maximum 200 words. All questions are compulsory. Each question carries 11 (Eleven) Marks.

प्रश्न. 3.5

उत्तर

आपदा संसाधनों के सुविधाजनक वितरण के कारण एक क्षेत्र का अत्यधिक विकास व किसी अन्य क्षेत्र का पिछड़ेपन की अवस्था में बने रहना क्षेत्रीय असंतुलन है, इसके कुछ प्रमुख कारण निम्न है,



प्राकृतिक कारण - पहाड़ी क्षेत्रों, दुर्गम वनों, सूखा, बाढ़, रेगिस्तान इत्यादि परिवहन के साधनों के विकास को अवरुद्ध करता है

मानव निर्मित अकाल
- सरकार की विकासपरक नीतियाँ,
- अदूरदर्शी औद्योगिक नीतियाँ,
- विस्थापनकारी नीतियाँ;
- प्रथम हरित क्रांति में कुछ ही क्षेत्रों जैसे पंजाब, हरियाणा आदि का विकास कुछ क्षेत्र तथा क्रांति से पहले थे।
- उद्योगों का कुछ ही क्षेत्रों जैसे दिल्ली मुंबई में केन्द्रण।

(10)

ऐतिहासिक व औपनिवेशिक कारण
- ब्रिटिश शासन की आर्थिक शोषणकारी नीतियाँ जैसे - विऔद्योगीकरण, कृषि का वाणिज्यिकरण आदि,
- कुछ क्षेत्रों में मालिकों का विशेष हरितक्रांति का विकास,

अतः क्षेत्रीय असंतुलन मानव के मनःमस्तिष्क में असंतुष्टि की भावना उत्पन्न करती है इस समस्या से निपटने हेतु समान व उचित विकास को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।

V good

ROUGH WORK

खण्ड – ब

प्रश्न.1 इस प्रश्न में 15 अति लघु उत्तरीय उप प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर अधिकतम 10 शब्दों में देना है। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न 03 (तीन) अंक का है।

Que.1 This question contains 15 very short answer type sub questions. Answer each question in maximum 10 words. All questions are compulsory. Each question carries 03 (Three) Marks.

प्रश्न.1.1 अनुच्छेद – 20

उत्तर ~~संविधान के भाग-3 में वर्णित मूल अधिकार,~~
~~अपराध के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण तीन अन्य प्रावधान~~
~~① कोई पूर्व प्रभाव कानून नहीं, ② कोई प्रति नहीं ③ स्व अभिशंसन नहीं,~~

3

प्रश्न.1.2 विधि का शासन

उत्तर ~~भारतीय संविधान के अनुच्छेद -14 द्वारा व्याख्यायित,~~
~~कोई विशेषाधिकार नहीं, कानून के समक्ष समता तथा~~
~~कानून सर्वोपरी होगा।~~

2

प्रश्न.1.3

उत्तर ~~भारतीय संविधान के भाग- 4 नीति निदेशक तत्वों में वर्णित,~~
~~इन्हें को न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं किया जा सकता~~
~~राज्य कानून द्वारा इन्हे प्रवर्तनीय बनाए तथा शासन के लिए मूल तत्व~~

3

अनु. 37 के संदर्भ से ही लिखे।

प्रश्न.1 इस प्रश्न में 15 अति लघु उत्तरीय उप प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर अधिकतम 10 शब्दों में देना है। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न 03 (तीन) अंक का है।

Que.1 This question contains 15 very short answer type sub questions. Answer each question in maximum 10 words. All questions are compulsory. Each question carries 03 (Three) Marks.

प्रश्न. 1.4

उत्तर (उच्चतम न्यायालय) (उच्च न्यायालय)

- संविधान के अनुच्छेद - 32 व अनुच्छेद 226 के तहत वर्णित,
- मूल अधिकारों के हनन के मामले में न्यायालय (5) रिट जारी करता है
(1) बंदी प्रत्यक्षीकरण (2) प्रतिषेध (3) अधिकार पृच्छा (4) उत्प्रेषण (5) परमादेश

प्रश्न. 1.5

उत्तर
- 26 जनवरी 1950, संविधान प्रवर्तन पश्चात् निर्मित विधि,
- अनु-13(2) - मूल अधिकारों से असंगत विधि शून्य घोषित,
- प्रत्येक उत्तर संवैधानिक विधियाँ 'प्रख्यकरण' व 'ग्रहण' सिद्धान्त का अनुपालन,

प्रश्न. 1.6

उत्तर अति गरीब वर्गों को अति आवश्यक खाद्यान्न वस्तुएँ जैसे,
- चावल, गेहूँ अनाज (उड़द दाल) पर्याप्त सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से, केन्द्र प्रायोजित। वर्ष 2000 में प्रारंभ योजना,

प्रश्न.1 इस प्रश्न में 15 अति लघु उत्तरीय उप प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर अधिकतम 10 शब्दों में देना है। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न 03 (तीन) अंक का है।

Que.1 This question contains 15 very short answer type sub questions. Answer each question in maximum 10 words. All questions are compulsory. Each question carries 03 (Three) Marks.

प्रश्न. 1.7

उत्तर - उपभोक्ता एवं खाद्य मंत्रालय के अंतर्गत एक अक्टूबर 2007 में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने केन्द्र प्रायोजित मिशन,
- 12th पंचवर्षीय योजना - 20 मिलियन टन खाद्यान्न उत्पादन लक्ष्य

(3)

प्रश्न. 1.8

उत्तर अति आवश्यक खाद्यान्न वस्तुएँ गेहूँ, चावल मोटे अनाज only उचित दाम पर उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराने हेतु प्रणाली, 1960 के दशक में प्रारंभ → 1992 - RPDS → 1997 → TPDS

(2½)

प्रश्न. 1.9

उत्तर भारतीय खाद्य अधिनियम, 1964 केन्द्रीय वर्ष 1965 में स्थापित सांविधिक निकाय, कार्य - किसानों से MSP पर खाद्यान्न खरीद → भण्डारण → वितरण व निर्गत मूल्य पर राज्य सरकारों को देना।

(3)

प्रश्न.1 इस प्रश्न में 15 अति लघु उत्तरीय उप प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर अधिकतम 10 शब्दों में देना है। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न 03 (तीन) अंक का है।

Que.1 This question contains 15 very short answer type sub questions. Answer each question in maximum 10 words. All questions are compulsory. Each question carries 03 (Three) Marks.

प्रश्न.1.10

उत्तर संशोधनों के ~~सुझावतम~~ दोहन द्वारा एक देश के अधिक विधेय व विधि अन्य देश का विधान भी प्रक्रिया में पिछड़ जाना। (2)

प्रश्न.1.11

उत्तर - अनुच्छेद 50 के अंतर्गत कार्यपालिका व न्यायपालिका के मध्य।
- सर्वप्रथम - मोंटेस्क्यू द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्त।
- भारत में लोचशील शक्ति का पृथक्करण - अवरुद्ध व संतुलन के साथ। (3)

प्रश्न.1.12

उत्तर - संविधान की सातवीं अनुसूची द्वारा विधायी शक्तियों का विभाजन, केन्द्र व उसकी एजेंसियों के मध्य शक्तियों का स्पष्ट विभाजन किया गया तीन सूची - केन्द्र, समवर्ती, राज्य (3)

नमूनार्थ प्रश्नोत्तर पुस्तिका
Sample Question
Answer Booklet

प्रश्नोत्तर पुस्तिका बारकोड / QR CODE/ Page No. 34

प्रश्न.1 इस प्रश्न में 15 अति लघु उत्तरीय उप प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर अधिकतम 10 शब्दों में देना है। सभी प्रश्न अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न 03 (तीन) अंक का है।

Que.1 This question contains 15 very short answer type sub questions. Answer each question in maximum 10 words. All questions are compulsory. Each question carries 03 (Three) Marks.

प्रश्न.1.13

उत्तर (1) लोगों द्वारा प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित।
(2) संवैधानिक प्रमुख वेशानुगत नहीं होगा।
(3) विशेषाधिकार वर्ग की समाप्ति।

प्रश्न.1.14

उत्तर राज्यों का संघ से तात्पर्य - ~~संघ~~ भारतीय संघ विदेशी समझौते का परिणाम नहीं और राज्यों के संघ से पृथक होने का अधिकार नहीं।

प्रश्न.1.15

उत्तर - ~~संविधान~~ संविधान के भाग-3 में वर्णित मूल अधिकार,
- प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार,
- निजता का अधिकार, विदेश भ्रमण का अधिकार शामिल।

प्रश्न.2 इस प्रश्न में 10 लघुउत्तरीय उपप्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर अधिकतम 50 शब्दों में देना है। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न 05 (पाँच) अंक का है।

Que.2 This question contains 10 short answer type sub questions. Answer the question in maximum 50 words. All questions are compulsory. Each question carries 05 (Five) Marks.

प्रश्न. 2.1

उत्तर सार्वजनिक वितरण प्रणाली के उद्देश्य -

(1) देश में लाभार्थियों को खाद्यान्न उपलब्ध कराना।

(2) बाजार में खाद्यान्न की कीमतों के उतार-चढ़ाव से नागरिकों को प्रभावित रखना।

(4) तंत्रित वर्ग

(3) नागरिकों के पोषाहार स्तर को उच्च बनाए रखना।

(4) भारतीय संविधान के अनुच्छेद-47 को मूर्तरूप देना।

(5) खर्च सुरक्षा, बफर स्टॉक व खाद्यान्नों राज्य की धारणा।

प्रश्न.2 इस प्रश्न में 10 लघुउत्तरीय उपप्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर अधिकतम 50 शब्दों में देना है। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न 05 (पाँच) अंक का है.

Que.2 This question contains 10 short answer type sub questions. Answer the question in maximum 50 words. All questions are compulsory. Each question carries 05 (Five) Marks.

प्रश्न.2.2

उत्तर ~~भारतीय खाद्य निगम की स्थापना 1965 में की गई, कार्य निम्न है~~—

(1) किसानों से MSP पर खाद्यान्न खरीद करना,
(2) खाद्यान्न भंडारण, परिवहन व वितरण करना,
(3) केन्द्रीय निर्गम मूल्य पर राज्य सरकारों को खाद्यान्न आपूर्ति सुनिश्चित करना,
(4) बफर स्टॉक की नीति द्वारा देश को आपात स्थिति में खाद्यान्न से लड़ने में सक्षम बनाना,
(5) खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 को प्रभावी बनाने केन्द्र व राज्य सरकार के बीच कड़ी के रूप में कार्य करना।

5

Good

प्रश्न. 2 इस प्रश्न में 10 लघुउत्तरीय उपप्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर अधिकतम 50 शब्दों में देना है। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न 05 (पाँच) अंक का है।

Que.2 This question contains 10 short answer type sub questions. Answer the question in maximum 50 words. All questions are compulsory. Each question carries 05 (Five) Marks.

प्रश्न. 2.3

उत्तर जनहित याचिका के उद्देश्य निम्नलिखित हैं:-

(1) तृतीय पक्ष के हितों का पोषण व अधिकारों की रक्षा,

(2) कार्यपालिका व विधायी विधायिका को अपने कार्यों के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु निर्देश देना,

(3) संविधान के प्रावधानों की गतिशील व्याख्या करना, जैसे - विशाखा वाद 1997 इत्यादि,

(4) न्यायाधीशों को जनाधार हेतु प्रोत्साहित करना,

(5) मूल अधिकारों को अर्थपूर्ण रूप में प्राप्त करना

नमूनार्थ प्रश्नोत्तर पुस्तिका
Sample Question
Answer Booklet

प्रश्नोत्तर पुस्तिका बारकोड / QR CODE / Page No. 38

प्रश्न 2 इस प्रश्न में 10 लघूउत्तरीय उपप्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर अधिकतम 50 शब्दों में देना है। सभी प्रश्न अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न 05 (पाँच) अंक का है।

Que.2 This question contains 10 short answer type sub questions. Answer the question in maximum 50 words. All questions are compulsory. Each question carries 05 (Five) Marks.

प्रश्न 2.1

उत्तर

लोक अदालत	स्थायी लोक अदालत
(1) राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण 1987 के तहत गठित निकाय,	राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण संशोधन 2002 के तहत गठन,
(2) पक्षों द्वारा दिए गए निर्णयों के खिलाफ किसी अन्य न्यायालय में अपील नहीं की जा सकती,	(2) निर्णय के खिलाफ किसी न्यायालय में अपील की जा सकती है,
(3) समाधेय मामलों में सुनवाई करता है,	(3) लोकोपयोगी सेवाओं के मामले में सुनवाई,

प्रश्न. 2 इस प्रश्न में 10 लघुउत्तरीय उपप्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर अधिकतम 50 शब्दों में देना है। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न 05 (पाँच) अंक का है।

Que.2 This question contains 10 short answer type sub questions. Answer the question in maximum 50 words. All questions are compulsory. Each question carries 05 (Five) Marks.

प्रश्न. 2.4

उत्तर भारतीय संघवाद की मूलभूत विशेषताएँ निम्नलिखित हैं-

(1) दोहरी सरकार - केन्द्र सरकार व राज्य सरकार,
(2) संविधान की सर्वोच्चता
(3) न्यायपालिका की स्वतन्त्रता
(4) राज्यसभा की उपस्थिति
(5) संविधान की सातवीं अनुसूची
(6) केन्द्र व राज्यों के मध्य शक्तियों का स्पष्ट विभाजन, इत्यादि।

नमूनार्थ प्रश्नोत्तर पुस्तिका
Sample Question
Answer Booklet

प्रश्नोत्तर पुस्तिका बारकोड / QR CODE/ Page No. 40

प्रश्न. 2 इस प्रश्न में 10 लघुउत्तरीय उपप्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर अधिकतम 50 शब्दों में देना है। सभी प्रश्न अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न 05 (पाँच) अंक का है।

Que.2 This question contains 10 short answer type sub questions. Answer the question in maximum 50 words. All questions are compulsory. Each question carries 05 (Five) Marks.

प्रश्न. 2.6

उत्तर

संसदीय शासन प्रणाली	अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली
(1) शासन के तीनों अंगों के मध्य शक्तियों का स्पष्ट पृथक्करण। (3)	(1) शासन के तीनों अंगों के मध्य शक्तियों का स्पष्ट पृथक्करण।
(2) कार्यपालिका का उद्भव विधायिका से होता है।	(2) कार्यपालिका व विधायिका के मध्य स्पष्ट विभाजन।
(3) मंत्रिपरिषद व प्रधानमंत्री जनता द्वारा के प्रतिनिधि	(3) राष्ट्रपति का निर्वाचन जनता द्वारा प्रत्यक्ष व परोक्ष रूप से।

प्रश्न. 2 इस प्रश्न में 10 लघुउत्तरीय उपप्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर अधिकतम 50 शब्दों में देना है। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न 05 (पाँच) अंक का है।

Que.2 This question contains 10 short answer type sub questions. Answer the question in maximum 50 words. All questions are compulsory. Each question carries 05 (Five) Marks.

प्रश्न. 2.6

उत्तर अनुच्छेद 14 की विषय वस्तु

— (1) विधि के समक्ष समता —

— (2) विधियों के समान संरक्षण —

किसी भी व्यक्ति को नागरिक विधिक या सामान्य दर्जा कुछ भी हो प्रथम वाक्य के द्वारा उसके साथ किसी भी परिस्थिति में समान व्यवहार किया जाएगा, द्वितीय वाक्य यह स्पष्ट करता है कि सभी नागरिकों के मध्य समान परिस्थितियों में समान व असमान परिस्थितियों में असमान व्यवहार किया जा सकता है,

(3)

प्रश्न. 2 इस प्रश्न में 10 लघुउत्तरीय उपप्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर अधिकतम 50 शब्दों में देना है। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न 05 (पाँच) अंक का है।

Que.2 This question contains 10 short answer type sub questions. Answer the question in maximum 50 words. All questions are compulsory. Each question carries 05 (Five) Marks.

प्रश्न. 2.8

उत्तर

संघ सूची के विषय

↳ रक्षा, विदेश, अंतरिक्ष,

वर्तमान में कुल - 97 विषय शामिल।

(7) राज्य सूची के विषय

↳ शिक्षा, पुलिस, स्थानीय निकाय,

वर्तमान मे राज्य सूची में कुल (62) विषय है।

प्रश्न. 2 इस प्रश्न में 10 लघुउत्तरीय उपप्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर अधिकतम 50 शब्दों में देना है। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न 05 (पाँच) अंक का है।

Que.2 This question contains 10 short answer type sub questions. Answer the question in maximum 50 words. All questions are compulsory. Each question carries 05 (Five) Marks.

प्रश्न. 2.8)

उत्तर वर्ष 1934 में मानवेन्द्र नाथ रॉय ने संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव तैयार, प्रस्तुत किया। इसके पूर्व भी वर्ष 1928 में इस हेतु प्रयास किए गए।

(4) वर्ष 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा के गठन को मंजूरी दी।

संविधान सभा - कुल सदस्य - 389 - 292 ब्रिटिश प्रांतों, 93 देशी रियासतों व 4 चीफ कमिश्नर प्रोविंसेज से।

संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों द्वारा किया गया।

- कैबिनेट मिशन 1946 द्वारा

प्रश्न. 2 इस प्रश्न में 10 लघुउत्तरीय उपप्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर अधिकतम 50 शब्दों में देना है। सभी प्रश्न अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न 05 (पाँच) अंक का है।

Que.2 This question contains 10 short answer type sub questions. Answer the question in maximum 50 words. All questions are compulsory. Each question carries 05 (Five) Marks.

प्रश्न. 2.10

उत्तर वाणिज्यिक गतिविधियों व लेन देन प्रणाली में ~~व~~ पैसे ~~के~~ या मुद्रा का प्रचलन सदा ~~रहा~~ वस्तु एवं सेवाओं की खरीद, बिक्री हस्तांतरण प्रणाली कहलाता है।

लाभ - बाजार में मुद्रा के प्रवाह को बनाए रखना,
हानि - समानांतर अर्थव्यवस्था, काला धन, टैक्स फ्रॉडिंग इत्यादि,
समाधान - एलीट्स करेंसी व सार्वभौमिक क्रीप्टो प्रणाली ब्लॉकचेन तकनीक का आगमन)

नमूनार्थ प्रश्नोत्तर पुस्तिका
Sample Question
Answer Booklet

प्रश्नोत्तर पुस्तिका बारकोड /QR CODE/ Page No. 45

प्रश्न. 2 इस प्रश्न में 10 लघुउत्तरीय उपप्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर अधिकतम 50 शब्दों में देना है। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न 05 (पाँच) अंक का है।

Que.2 This question contains 10 short answer type sub questions. Answer the question in maximum 50 words. All questions are compulsory. Each question carries 05 (Five) Marks.

प्रश्न 2.10

उत्तर

प्रश्न.3 इस प्रश्न में 5 दीर्घउत्तरीय या निबंधात्मक उपप्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर अधिकतम 200 शब्दों में देना है। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न 11 (ग्यारह) अंक का है।

Que. 3 This question contains 5 long answer or essay type sub questions. Answer each question in maximum 200 words. All questions are compulsory. Each question carries 11 (Eleven) Marks.

प्रश्न. 3.1

उत्तर

अति आवश्यक व्यक्तियों के पास पहुँचेगी, चाहे वे मीलों अनाज वितरित केन्द्रों पर उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 1960 के दशक में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की शुरुआत की गई, जिसमें समय-समय पर अनेक सुधार किए गए। सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार हेतु सुझाव निम्न लिखित है— (10)

(1) सब्सिडी का सही लक्ष्य — केवल उचित लाभार्थी को ही सस्ता लाभ मिले।

(2) परिवहन एवं भंडारण व्यवस्था दुरुस्त करना — इसमें फ्रीड ट्रांसपोर्ट सिस्टम का प्रयोग व सील सिलोस एवं गोदाम की अधिक मात्रा में स्थापना।

(5) स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार वितरण प्रणाली को पुनर्गठित किया जाए। जैसे पोषणयुक्त भोजन व ग्रामीण क्षेत्रों में मोटे अनाज उपलब्ध का मुख्य आधार है।

(4) राशन कार्ड वर्तमान में कोटेदारों के अधीन है व राजनीतिक संरक्षण प्राप्त व्यक्तियों को प्रथमतः आवंटन किया जाता है, ऑनलाइन निगरानी प्रणाली के माध्यम से आवंटन किया जा सकता है।

(3) लाभार्थियों की पहचान का जिम्मा राज्य सरकार को सौंपा गया है, स्थानीय निकायों को लाभार्थियों की अच्छी समझ है अर्थात् उन्हें यह जिम्मा सौंपा जाए।

(6) लाभार्थियों की पहचान हेतु राष्ट्रीय डायबेज जैसे सॉफ्टवेयर को निर्मित किया जाए।

वाधवा समिति की सिफारिशों को पूर्ण रूप देकर PDS प्रणाली का पर्याप्त रिफॉर्मलीकरण किया जाना चाहिए यह आवश्यक ही खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करेगा अन्यथा असंभव है।

प्रश्न.3 इस प्रश्न में 5 दीर्घउत्तरीय या निबंधात्मक उपप्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर अधिकतम 200 शब्दों में देना है। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न 11 (ग्यारह) अंक का है।

Que. 3 This question contains 5 long answer or essay type sub questions. Answer each question in maximum 200 words. All questions are compulsory. Each question carries 11 (Eleven) Marks.

प्रश्न. 3.2

उत्तर

जनहित याचिका के माध्यम से न्यायालय संविधान के मूल प्रावधानों की पुनर्व्याख्या करते हैं व नवाचार, विधायी निर्वात के क्षेत्र में नए प्रतिमानों को स्थापित कर न्याय सुनिश्चित करती है।

(3)

जनहित याचिका की प्रकृति -

(1) गैर- एडवर्सरी - किसी घटना, अन्वेषण, अधिकारी की रिपोर्ट को आधार बनाकर जनहित याचिका प्रेषित की जा सकती है।

(2) नॉन एडिशनरी - अर्थात तृतीय पक्ष की याचिका, जिसका अर्थ है कि जनहित याचिका किसी तीसरे पक्ष द्वारा अन्य दो पक्षों के हितों के पोषण हेतु प्रेषित की जाती है।

(3)

प्रश्न.3 इस प्रश्न में 5 दीर्घउत्तरीय या निबंधात्मक उपप्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर अधिकतम 200 शब्दों में देना है। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न 11 (ग्यारह) अंक का है।

Que. 3 This question contains 5long answer or essay type sub questions. Answer each question in maximum 200 words. All questions are compulsory. Each question carries 11 (Eleven) Marks.

प्रश्न. 3.~~2~~ 3

उत्तर

न्यायिक सक्रियता से आशय न्यायपालिका द्वारा विधियों के निर्वचन हेतु आगे बढ़कर भूमिका लेने से है, न्यायिक सक्रियता के माध्यम से न्यायपालिका संविधान के प्रावधानों की प्रगतिशील व्याख्या करती है एवं ~~के~~ नागरिक अधिकारों को सार्थक रूप में प्रदान करती है।

7

सार्वजनिक हित व सामाजिक समावेशीकरण में न्यायिक सक्रियता के प्रभाव -

- 'अभय बंसल वाद 2018 में सर्वोच्च न्यायालय ने ~~मत दिया~~ कार्यपालिका या सरकार को निर्देश दिया कि वह उत्तराखंड में ~~जंगल~~ बाघ पीड़ितों के लिए हेलिकॉप्टर की व्यवस्था करे। सार्वजनिक हित सुनिश्चित किया।

- विशाखा बनाम राजस्थान मामले में उच्चतम न्यायालय ने कार्यस्थल पर महिलाओं के शोषण से रक्षा हेतु विशाखा गाइडलाइन्स निर्मित की जो सामाजिक समावेशीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास था।

- अरुणाचल मामले में उच्चतम न्यायालय ने पर्यावरण सुरक्षा के अनुमति प्रदान कर मूल अधिकारों के साथ विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को के सिद्धांत को बनाए रखा।

अतः उच्चतम न्यायपालिका व्यापक व्याख्या द्वारा विधायी निर्वात के क्षेत्र में मार्गदर्शक सिद्धांतों का प्रतिपादन कर सर्वव्यापक हित सामाजिक समावेशीकरण को बनाए रखने में अपनी सकारात्मक भूमिका निभाती है।

प्रश्न.3 इस प्रश्न में 5 दीर्घउत्तरीय या निबंधात्मक उपप्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर अधिकतम 200 शब्दों में देना है। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न 11 (ग्यारह) अंक का है।

Que. 3 This question contains 5 long answer or essay type sub questions. Answer each question in maximum 200 words. All questions are compulsory. Each question carries 11 (Eleven) Marks.

प्रश्न. 3.1

उत्तर

भारतीय संविधान के भाग-5 में अनुच्छेद -124-147 के मध्य सर्वोच्च न्यायालय का प्रावधान किया गया है, विधि के निर्वचन: व्याख्या व इसे लागू करने की शक्ति ही न्यायालय की प्राधिकारिता कही जाती है इसके अंतर्गत ही न्यायालय संघ व इसकी इकाईयों के मध्य विवाद व अन्य विवादों को सुनवाई करता है, सर्वोच्च न्यायालय की प्रमुख प्राधिकारिता निम्न है-

(1) अनुच्छेद - 129 - अभिलेख न्यायालय इसके निर्णय लेखबद्ध होंगे इनका विधानिक मूल्य होगा अन्य न्यायालय अपने निर्णयों में इनको संदर्भ के रूप में प्रयोग करेंगे।

अनुच्छेद - 132 - संवैधानिक मामले में अपील

अनुच्छेद - 133 - सिविल मामले में अपील

अनुच्छेद - 134 - दाण्डिक मामले में अपील

अनुच्छेद - 136 - विशेष अनुमति
देने की शक्ति न्यायालय से अपने मामले की सुनवाई हेतु अपील करवाना है। अनुमति देना न्यायालय का विशेषाधिकार है।

अनुच्छेद - 137 - पुनर्विलोकन संबंधी प्राधिकरण
न्याय सर्वोच्च न्यायालय अपने ही निर्णय, निर्वचनों का पुनर्विलोकन कर सकता है।

अनुच्छेद - 143 - परामर्शदात्री प्राधिकरण
संविधान पूर्व या पश्चात निर्मित विधि के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश भारत के राष्ट्रपति को परामर्श दे सकता है, निर्णय राष्ट्रपति पर बाध्यकारी नहीं होगा।